development can take place so that poor people from one country do not migrate to other countries. Now, this principle is really acceptable. But its implementation is not very easy.

SHRI BALBIR K. PUNJ: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I have seen the Minister's reply and part (c) of the reply says that the Government has decided to appoint a Group of Ministers to study the implications of this Supreme Court judgement. Sir, somewhere this reply shows that the Government is not sincere in implementing the direction of the Supreme Court and this is a covert attempt to bypass the Supreme Court judgement. ...(*Interruptions*)... The problem of Bangladeshi infiltration is less of economic ...(*Interruptions*)... No, Sir. ...(*Interruptions*)... Will the hon. Minister clarify the position that the Government will implement the Supreme Court's direction in letter and spirit?

श्री सभापति: वह लागू होगा।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have no hesitation in saying that the Supreme Court decision will be implemented in letter and spirit. That has been our policy and that will be our policy. Having said this, I shall have to bring to the notice of this august House that there are complaints made by genuine Indian citizens. They say because they speak Bengali language, they are treated as Bangladeshis. And that is why they say that sort of injustice is being done to them. Now, this is an aspect, which cannot be neglected by any sensitive Government. We want to see that we would like to implement the Supreme Court judgement in full spirit. Yet if there are genuine difficulties faced by genuine persons, they are looked into for assistance that can be given.

*147. [The questioners (Dr. Murli Manohar Joshi and Shri Ram Jethmalani) were absent. For answer *vide* page 34]

"Bharat Nirmaı." scheme

*148. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently a detailed programme for the renewal of rural infrastructure, with a massive initial investment

of Rs. 1,74,000 crores, under the composite "Bharat Nirman" scheme has been formulated; and

(b) if so, the details thereof, including the critical areas of rural infrastructure identified for special focus, the time-frame fixed for implementation and the sources of funding decided upon?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The formulation of "Bharat Nirman" Programme was announced by the Finance Minister in his Budget Speech in the Union Budget 2005-06. The total investment required for the various components of Bharat Nirman has been estimated to be about Rs. 1,74,000 crores.

(b) The critial areas of rural infrastructure identified for special focus and their details are as follows:—

Irrigation	To create one crore ha. additional irrigation.
Rural Drinking Water	To provide potable drinking to 55067 uncovered habitations (as per revised assessment), slipped back habitations, quality affected habitations and rural schools.
Rural Roads	To connect all villages that have a population of 1000 (or 500 in hilly tribal areas) with road.
Rural Housing	To construct 60 lakh additional houses for the poor.
Rural Eelctrification	To electrify remaining 1,25,000 villages and offer electricity connection to 2.3 cr. households.
Rural Telephone Connectivity	To give telephone connectivity to remaining 66822 villages.

Bharat Nirman is a 4 year programme which is scheduled to be completed by 2008-09. However, while the Rural Road Programme would need one more year, the programme of Rural Electrification would extend till the end of the Eleventh Plan. Rural Telephone Connectivity is proposed

to be completed in 3 years. The additional fund requirements will be met through an appropriate mix of budgetary support, external aid, market borrowing and beneficiary contribution (in some cases).

श्री आर० पी० गोयनका: सर, मेरा पहला सवाल है कि यह प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इसका आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, ''भारत निर्माण'' की योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दो बार बैठकें हुई हैं, जिसमें क्या बजट उपबंध अभी मौजूद है और क्या बजट में बढ़ोतरी आएगी, इस सब पर विचार हुआ है। फाइनेन्स विभाग ने अपनी सहमति जाहिर की है कि हम उसका प्रबंध करेंगे और योजना कार्यान्वयन शुरू है।

श्री सभापति: अब तक इस योजना में कितना रुपया खर्च हुआ है, कितना रुपया दिया है?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसमें चार-पांच वर्षों में कुल 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपया खर्चा लगना है। इसमें जो अपना बजट रूटीन पहले से मौजूद है, महोदय, उसके अलावा 82 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त उसमें चाहिए। तो उसका प्रबंध किया जा रहा है।

श्री सभापति: नहीं। आप रुपये का प्रबंध तो कर रहे हैं, यह दूसरा प्रश्न है। जो प्रबंध हो चुका है, उसमें से आपने कितना दिया है?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: जो उसमें प्रथम वर्ष का बजट उपबंध है, उतना दिया जा चुका है।

श्री सभापति: कितना।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: जैसे, महोदय, उसमें 6 आइटम हैं। इनमें एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसमें अभी 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। महोदय, 6 आइटम हैं उसमें।

श्री सभापति: वह तो ठीक है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, एक प्रधानमंत्री ग्राम योजना में 1000 तक की आबादी को चार वर्षों के अंदर सड़क से कनेक्शन दे देना है और पहाड़ी एरिए की 500 तक की आबादी को। उसमें कुल 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें से 4200 करोड़ रुपया बजट उपबंध है, लेकिन उसका एडीशनल ...(व्यवधान)... आप सुन तो लीजिए।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। बिना पूछे अगर आप बोलेंगे, तो रिकॉर्ड नहीं होगा।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: तो, महोदय, इन 6 आइटम में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।

श्री सभापति : वह सब तो समझ गए। आप तो टोटल बता दीजिए कि जो कुछ भी योजना हैं, उसके अगेन्स्ट में अब तक आपने टोटल कितना रुपया दे दिया है?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, उसमें जो 6 आइटम हैं, उसमें जो बजट उपबंध है, ...(व्यवधान)... जो बजट उपबंध है, वह दिया गया है। ...(व्यवधान)... अरे, सुनिए तो। ...(व्यवधान)... महोदय, 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए में 82 हजार करोड़ रुपया जो अतिरिक्त है, उसका उपबंध किया जा रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो राशि है, उसका चौथा हिस्सा सभी बजट के लिए उपबंध कर दिया गया है और खर्चा किया जा रहा है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो आपने पूछा, उसका भी जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप बैठ जाइए. ...(व्यवधान)... एक मिनट बैठ जाइए। माननीय सदस्य, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं करते हैं, डिसक्रिमिनेशन हो जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सर, आपने जो पूछा, उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री सभापति: अच्छा, नहीं दिया, तो मुझे चिंता होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... बैठिए। बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए।

श्री राजू परमार: हमने आपका भी ''इंडिया शाइनिंग'' देखा था। ...(व्यवधान)... और फील गुड फैक्टर। ...(व्यवधान)...

श्री आर॰ पी॰ गोयनका: सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री सभापति: ऐसा सवाल करना कि जवाब मिल जाए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: पहले का मिला या नहीं? ...(व्यवधान)

श्री आर॰ पी॰ गोयनका: सर, पहले का तो मिल गया है, 22 हजार करोड़ रुपए की बात है। 22 हजार करोड़ रुपया पहले साल में मिल गया है, यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए सरकार को और मंत्री जी को, दोनों का धन्यवाद दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, शांति रखें।

श्री आर० पी० गोयनका: पैसा नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? क्या बात करते हैं आप? ...(व्यवधान)... सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह जो 6 आइटम हैं, इसमें मंत्री जी क्या अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू कोई कंट्रोल रख रहे हैं? मैं इनमें एक आइटम पर बोलना चाहता हूँ और वह है पावर। अगर कोयला नहीं मिलेगा, उसकी लिंक नहीं होगी, तो पावर नहीं होगा और फिर तीन साल बाद हमको यह कहा जाए कि पावर-प्लांट ही नहीं आए हैं, तो यह दुख की बात होगी। इसलिए मैं आपके थ्रू मंत्री महोदय को बहुत हम्बली यह एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, इन 6 आइटम में माननीय सदस्य ने एक ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली के संबंध में पूछा और इन्होंने चिंता जाहिर की है। जो 6 लाख गांव में सवा लाख गांव बचे हुए हैं, जहां बिजलीकरण नहीं हुआ है, वहां बिजलीकरण का इस ''भारत निर्माण'' योजना में प्रावधान किया गया है।

पैसे का भी प्रबंध किया गया है, कार्य आरम्भ भी हो चुका है। महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के बाद इसमें विद्युत की आपूर्ति हो, इस ओर माननीय सदस्य ने ध्यान खींचा है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हम जेनरेशन में तीन तरह का ध्यान देने के बारे में देखेंगे – ग्रामीण विद्युतीकरण के बाद जेनरेशन थर्मल पावर प्लांट, पन-बिजली योजना और न्यूक्लिअर पावर प्लांट। हम चाहते हैं कि सभी से इतने विद्युत उत्पादन का प्रबंध हो कि गांवों में बिजली-आपूर्ति में कमी न हो सके।

श्री ललितभाई मेहता: कोयला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, बिना अनुमति के न बोलें।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट पेश किया था, तो उसमें उन्होंने भारत निर्माण का ज़िक्र किया था और 6 विषय-बिन्दु जो इसके हैं, जिनका उल्लेख मंत्री जी ने यहां किया, उनका उल्लेख उन्होंने बजट में किया था। उस समय हम लोगों ने शिकायत की थी क्योंकि बजट में इनके लिए क्या प्रावधान हैं, उसका उल्लेख बजट में नहीं था। मंत्री महोदय आज हम लोगों को सूचना दे रहे हैं कि जो स्कीमें चल रही हैं पहले से, जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ज़िक्र किया, यह योजना पहले से चल रही है, यह 2001 में शुरू हुई थी, उसके लिए प्रावधान हर साल के बजट में किया जाता है। अन्य जो पांच बिन्दु हैं, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण है, उसके लिए भी हर साल प्रावधान किया जाता है। इन सब प्रावधानों को मिलाकर इन्होंने बताया है 20 या 22 हजार, उन्होंने नहीं कहा, गोयनका जी ने कहा कि इसका प्रावधान किया गया है और खूब ताली बजीं, हम लोग भी खुश हैं कि इतने का प्रावधान है। लेकिन, मंत्री महोदय ने कहा कि 84 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए इसके कार्यान्वयन के लिए। अगर 84 हजार करोड़ रुपए लगभग चार वर्षों में चाहिए तो मुझे लगता है कि 21, 22 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसमें खर्च होने

चाहिएं इस साल से अतिरिक्त और इन्होंने बताया कि वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है, बातचीत हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस साल जो प्रावधान हैं, क्योंकि सप्लिमेंट्री बजट कल आ गया है, वह हम लोगों के सामने है, उसमें मैंने कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं देखा, तो क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 22, 24 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसके लिए चाहिए, उनमें से इस साल के लिए अतिरिक्त प्रावधान क्या है या क्या होने जा रहा है?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, उसमें आइटमवाइज़, जैसे पीने का पानी है, पहले ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: पहले इनको पानी पिला दो आप।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, 6 आइटम्स हैं, उन 6 आइटम्स का अलग-अलग एक साथ बता देता हूं।

श्री सभापति: एक साथ ही बता दीजिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इस साल सब जोड़कर करीब 6 हजार करोड़ अतिरिक्त बजट का उपबंध किया गया है।

श्री सभापति: ठीक है। हो गया।

श्री यशवंत सिन्हा: 6 हजार करोड़ रुपया 84 हजार में कहां खड़ा है?

श्री सभापति: अगला क्वेशचन। प्रश्न संख्या 149.

Steps to retain pilots of Armed Forces

*149. SHRI T.T.V. DHINAKARAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of pilots of Armed Forces who had quit the service during the last three years, showing the force each had served togetherwith the length of service;

(b) whether it is a fact that more and more pilots are leaving the forces for greener pastures with the MNCs 'outside'; and